

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
राजस्थान शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-१,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून, दिनांक ३० मई, २००८

विषय:- वित्तीय वर्ष २००८-०९ में जनपद देहरादून में देहरादून में मोथरोवाला (दाबा) से मदन प्रकाश सेमवाल के घर से पितृशरण बहुगुणा के घर तक सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग्राम. लो०नी०य० पीडी ने अपने पत्र रां०-१०४६/९याता-पव०/०७ दिनांक ०१.०३.०८, के द्वारा शासनादेश संख्या-१७१/१११(२)/०८-४२(प्रा.आ.) ०७ दिनांक १७.०१.०८ में कमाक १४८ पर रसीकृत उपरोक्त कार्य का आगणन स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है। मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रूपये ०४.१० लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त रूपये ०४.०७ लाख (रूपये चार लाख सात हजार भाव्र) की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गई है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्य हेतु टी०ए०सी० वित्त द्वारा आंकित रूपये ०४.०७ लाख (रूपये चार लाख सात हजार भाव्र) की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

२. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो डरें इन्डियूल आफ रेट में रसीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, जो स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यदाती की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कर्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

३. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानविक गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, विना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

४. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

५. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विनाम की स्वीकृति जिन कार्दों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

६. एकमुश्त प्राविधान को कार्द करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

७. कार्य करने से पूर्व रथल का भलीमौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्वेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात रथल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्द किया जाय।

८. आगणन में जिन मदों हेतु जो चारि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद का दूसरी मद में लाय कदापि न किया

३

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि को पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
13. इस तंबांध मे होने वाला व्यव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आव व्यवक से लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सङ्को तथा सेतुओं पर पूर्जीगत परिव्यव-04 जिला तथा अन्य सङ्को-आयोजनागत-800-अन्य व्यव-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे ढाला जायेगा।
14. शासनादेश की शेष सभी शहर शासनादेश संख्या-171/ 111(2)/ 08-42(प्रा.आ.) 07 दिनांक 17.01.08 के अनुसार व्याप्त रहेंगी।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव

संख्या-1610- (1) / 111(2) / 08-18(एम०एल०ए०) / 07, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित :-

1. नहालेखाकार (लेखा प्रधम), औदराय मोटर्स विलिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लोनिवि, पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, नवां वृत्त लोनिवि उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/ गाड़ बुक।

आज्ञा से,

द१ जून २०१५

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव